बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 1

समुचित प्रक्रिया जरूरी

लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर जैसे जटिल युद्धक हथियार खरीदने का काम आसान नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वायु सेना के लिए की गई मझोले लड़ाकू विमानों की खरीद के ऑर्डर पर 660 तथा रडार सिस्टम पर 42 विशेष टिप्पणियां की हैं। यह प्रक्रिया इतनी सीधी सपाट भी नहीं कि बिना सोच विचार पूरी कर ली जाए। क्योंकि तब अधिकांश बोली लगाने वाले एकबारगी ही अयोग्य घोषित हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी विशेषताएं या उत्पाद की विशिष्टताओं को महत्त्व दिया जा सकता है जो यह तय करने में मदद करें कि क्या बेहतर हो सकता है और क्या नहीं? यह अक्सर निर्णय से जुड़ा मामला होता है। वास्तविक तौर पर देखें तो उपयोगकर्ता की प्राथमिकता की भी एक अहमियत होती है। वायु सेना के साथ भी यही मामला है। शुरुआती चरण में उसने बार-बार इस बात पर जोर देना जारी रखा कि उसे मिराज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि करगिल युद्ध में इस विमान का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा था। क्या 2012 में मिराज के उत्तराधिकारी के रूप में राफेल के चयन के लिए भी वायु सेना का ऐसा ही दबाव था, हालांकि उस वक्त उसे कामयाबी नहीं मिल सकी।

यह दो ऐसी चीजों के बीच चयन हो सकता है जिनमें बहुत कम अंतर हो। यकीनी तौर पर यूरोफाइटर भी राफेल के समान ही बेहतर रहा होगा क्योंकि इसका भी चयन किया गया था, और स्वीडन की बोफोर्स गन का फ्रेंच विकल्प भी उतना ही दमदार रहा होगा। परंतु क्या यूरोफाइटर का चयन करने से उसे भारत के लिए खास जरूरतों के मुताबिक उन्नत नहीं बनाना पड़ता? और राफेल को इस रूप में ढालने में लगी 140 करोड़ डॉलर या कुछ अधिक की राशि खर्च नहीं करनी पड़ती? सबसे बढ़कर कूटनयिक निहितार्थ भी चयन को प्रभावित कर सकते हैं और करते हैं। आखिर इस बात की और क्या वजह हो सकती है कि भारवाहक हेलीकॉप्टरों की मानक दर बदली गई, वह भी बोलियां खोले जाने के बाद? ऐसे में एक ओर जहां अंकेक्षण की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, वहीं व्यावहारिक बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

ऑडिट रिपोर्ट भी हथियार खरीद की जटिल रिपोर्ट से आसान नहीं होतीं। ऐसे में यह समझ होनी आवश्यक है कि आखिर क्यों सीएजी रक्षा मंत्रालय के इस बात पर जोर देने पर चुपचाप मान गया कि राफेल अनुबंध में वित्तीय गोपनीयता का प्रावधान है। जबकि अन्य तमाम हथियार खरीद सौदों से जुड़े वित्तीय आंकड़े सीएजी की उसी रिपोर्ट में साफ देखे जा सकते हैं। यह भी जाहिर है कि सीएजी ने राफेल की वित्तीय गारंटी न दिए जाने के कारण हुई बचत की राशि का उल्लेख न कर भी सरकार को राहत दी है। अंकेक्षकों के लिए काफी कुछ है।

क्या हथियार खरीद की यह विस्तृत प्रक्रिया इसलिए कम गुणवत्ता की है क्योंकि यह इतनी विस्तृत है? इस समीकरण में समय को कारक मानकर देखिए। कई मामलों में चयन प्रक्रिया में ही 8 से 10 वर्ष का समय लगता है और इस दौरान रक्षा सेवाओं को प्रतीक्षा करनी होती है। कई बार तो इसके बाद भी खरीद को अंजाम नहीं दिया जाता। कई बार अंतरिम तौर पर तकनीक बदल चुकी होती है। क्या प्रतिस्पर्धी बोलियों के बीच चयन की संक्षिप्त प्रक्रिया संभव है? क्योंकि हाल के दिनों में तो अधिकांश खरीद बिना ऐसी बोली के हुई है। जहां तक लेनदेन की बात है, शायद ही कोई होगा जो सोचेगा कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले सौदों में पैसे का लेनदेन नहीं होता होगा। ध्यान रहे कि ये निर्णय कई स्तरों पर, कई वर्ष में लिए जाते हैं और चयन करना इतना जटिल होता है कि इनमें हेराफेरी की काफी गुंजाइश रहती है।

इस बीच बड़े सवालों का कोई उचित जवाब ही नहीं है। उदाहरण के लिए इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जब वायु सेना को 126 लड़ाकू विमानों की आवश्यकता थी तो 36 विमान क्यों खरीदे गए जबकि वैसे ही विमानों के लिए नए सिरे से बोली लगने तथा उनके हासिल होने में कई वर्ष का समय लग सकता है। रक्षा मंत्रालय ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है कि हल्के लड़ाकू विमानों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। यानी उसके हिसाब से मझोले और हल्के विमानों में कोई फर्क ही नहीं है। तेजस के मामले में भी धीमी प्रगति हो रही है। अब वायु सेना अतिरिक्त सुखोई-30 हासिल करने में लगा है जो भारी विमान हैं। इस बीच वायु सेना घरेलू विमान निर्माण उद्योग तैयार करने से निरंतर दूरी बनाए हुए है। नौसेना जहाज निर्माण के क्षेत्र में बहुत पहले स्वदेशी अपना चुकी है। यानी इतने भारी रक्षा बजट के बावजूद हमारा देश आयात पर निर्भर हो चुका है। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

विनय सिन्हा

पाकिस्तान ने खुद पर ही चला दी बंदूक

पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तान के लिए काफी बड़ा दांव बन गया है। लेकिन उसने यह दांव भारत में 'गलत' सरकार के दौरान खेला है।

दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विद्वान स्टीफन पी कोहन की पाकिस्तान की सामरिक सोच को लेकर एक अनूठी व्याख्या है। कोहन के मुताबिक, पाकिस्तान अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर दुनिया के साथ बातचीत करता है, मानो कहता हो कि 'जो मुझे चाहिए वह दे दो नहीं तो मैं अपना भेजा उड़ा लूंगा'। फिर आपको उसकी फैलाई गड़बड़ी से जूझना पड़ता है। क्या पाकिस्तान ने पुलवामा में उस बंदूक का ट्रिगर दबा दिया है?

पहली बात, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यह हमला घरेलू आतंक की उपज है। यह फिदायीन आतंकी एक मतांध भारतीय कश्मीरी था। इन वजहों से यह हमला पूरी तरह से भारतीयों द्वारा सोचा-समझा और अंजाम दिया हुआ नहीं हो सकता है:

हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है जो पूरी तरह पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई के निर्देशों से संचालित होने वाला संगठन है। भले ही कट्टरपंथ का असर और इसकी प्रेरणा स्थानीय हो सकती है लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक अनाड़ी स्थानीय समूहों के पास उपलब्ध रहा हो। उनके लिए विस्फोट ट्रिगर और टाइमर की कार्यप्रणाली को भी समझ पाना मुश्किल है। हमला अंजाम देने के पहले रिकॉर्ड वीडियो को देखिए। हमलावर की भाषा कश्मीरी अवाम की शिकायतों या बदले वाली न होकर बाकी हिस्सों के मुसलमानों को उकसाने वाली है। बाबरी मस्जिद और गुजरात का जिक्र किया गया है और 'गोमूत्र पीने वालों' के खिलाफ बगावत करने की अपील 'अपने सभी मुस्लिमों' से की गई है। यह लश्कर-ए-तैयबा की सोच से कहीं अधिक जैश की राय है, स्थानीय कश्मीरियों की तो कतई नहीं।

यह हमला जैश के पिछले कारनामों की शैली से पूरी तरह मेल खाता है। वर्ष 2001 में श्रीनगर में विधानसभा पर आत्मघाती हमला, उसी साल संसद भवन पर आतंकी हमला, पठानकोट और गुरदासपुर में हमला, सभी का मकसद आतंक को किसी तरह कश्मीर के बाहर ले जाना था। लश्कर ने भी नवंबर 2008 के मुंबई हमले में भी यही किया था लेकिन उसकी ज्यादा ताकत कश्मीर में लड़ाई जारी रखने में ही लग रही है। वैश्विक दबाव में लश्कर के सैन्य हुक्मरान उसे पाकिस्तानी राजनीति में लाना चाह रहे हैं। वहीं जैश आकार में छोटा होने के बावजूद अधिक खतरनाक, साधन-संपन्न और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का चहेता भी है। जैश 'असरदार' हमलों के चयन में भी अधिक सजग रहा है।

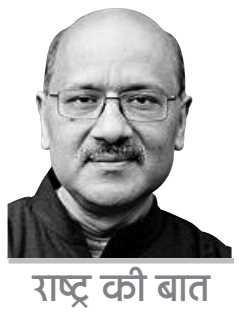

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

हम आईसी-814 विमान कांड से ही जैश की साधन-संपन्नता को जानते हैं। उसने काठमांडू से उड़ान भरने वाले इस भारतीय विमान को अगवा किया और सुरक्षित पनाहगाह कंधार तक ले गया। उसने यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के एवज में भारतीय जेलों में बंद बड़े आतंकी सरगनाओं की रिहाई की मांग रखी। कई अनुसंधानों में यह बात पुख्ता हो चुकी है कि अपहरणकर्ताओं को काठमांडू तक पहुंचाने, कंधार में तालिबान के जरिये बातचीत करने और जैश के सरगना मसूद अजहर की सुरक्षित रिहाई तक की समूची प्रक्रिया की निगरानी आईएसआई ने ही की थी। पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान और आईएसआई के लिए मसूद अजहर एवं जैश की अहमियत लश्कर और हाफिज सईद से कहीं अधिक है। जैश उसकी ताकत बढ़ाने वाला मुख्य संगठन है। चीन भी इस बात को मानता है इसीलिए वह शर्मनाक ढंग से उसका बचाव भी कर रहा है।

पुलवामा हमले के आत्मघाती युवक का स्थानीय होना कोई अचरज वाली बात नहीं है। अब तक के अपने सभी हमलों में जैश ने भारतीय कश्मीरियों की अहम भागीदारी रखी है। संसद हमले में शामिल रहा अफजल गुरु भारतीय ही था। ऐसे में स्थानीय संगठन की संलिप्तता और हमले की वजह खोजने में वक्त जाया होने से बचाने के लिए हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। पाकिस्तान भी उन्हें नकार नहीं सकेगा।

फिर उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या पाकिस्तान ने वाकई इस बार अपनी कनपटी पर रखी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया है? इससे पहले हुए जैश और लश्कर के सभी हमले घोषित जवाबी कार्रवाई के बगैर ही निकल गए हैं, हालांकि कुछ गोपनीय सर्जिकल स्ट्राइक जरूर हुई। वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौरान भारत बाध्यकारी कूटनीति, पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ाने और मूलत: शांतिवादी रवैया रखने वाली सामरिक मनोदशा के चलते अपने गुस्से भरे दौर से निकलने में सफल रहा था। भारत की सोच यही थी कि किसी भी उकसावे की कार्रवाई का हद से ज्यादा जवाब नहीं देना है। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा धीरज नहीं है। यह सरकार मनमोहन और वाजपेयी समेत पिछली तमाम सरकारों को उनकी 'कायरता' के लिए जिम्मेदार मानती रही है। उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मचे शोर और उससे हासिल राजनीतिक पूंजी को देखें तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वह खुद पर लंबे समय तक काबू रख पाने में सफल होगी। पाकिस्तान को जवाब मिलने जा रहा है। यह कोई नहीं जानता है कि ऐसा कब, कहां और कैसे होगा लेकिन इसमें लंबा वक्त भी नहीं लगेगा।

जवाबी कार्रवाई जल्द ही हो सकती है। यह सबकी नजरों में आने वाला, गहरे शोर वाला और विजयी बदले के दावों में लिपटा होगा। भारत में चुनाव अभियान शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में मोदी नहीं चाहेंगे कि दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जाने के पहले उन पर पुलवामा का दाग लगा रहे।

ऐसे में पाकिस्तान को यह फैसला लेना होगा कि वह मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाए या इसका जवाबी हमला शुरू कर जवाब दे। इसका सैन्य नतीजा कुछ भी हो लेकिन इससे इमरान खान का वर्तमान कार्यकाल खत्म हो जाएगा। हमें इतिहास बताता है कि कोई भी पाकिस्तानी नेता भारत के साथ छोटा-बड़ा युद्ध करके कुर्सी पर नहीं बना रह सकता है। इसका उदाहरण अयूब खान (1965), याह्या खान (1971) और नवाज शरीफ हैं। पाकिस्तान की बुनियादी हकीकत को लेकर ज्यादा तर्क नहीं हो सकते। इमरान को आखिरकार सेना/आईएसआई की जिद की कीमत चुकानी होगी, जिस तरह करगिल के लिए नवाज को चुकानी पड़ी थी। उन्हें बलि का बकरा बनने से बचने के लिए बहुत चतुराई और किस्मत की जरूरत होगी।

पाकिस्तान में ऐसे मसलों पर अंतिम फैसला निर्वाचित प्रधानमंत्री का नहीं होता है और इमरान तो पिछले कुछ वर्षों के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। फौरन जवाबी हमला करने का फैसला उनकी सेना करेगी। क्या वह उन्हें ऐसा न करने की सलाह भी दे सकते हैं, इसे लेकर हम सुनिश्चित नहीं हो सकते। सेना ही फैसला करेगी कि उसे जंग छेड़नी है या नहीं। इमरान तो किसी भी तरह नाकाम ही होंगे।

अब दो अन्य अहम फर्क भी हैं। पहला, अब दुनिया वर्ष 2008 या 2001-02 से बिल्कुल अलग है। तब शीर्ष अमेरिकी और यूरोपीय देशों के प्रमुख फोन करते थे। रूस और चीन जैसे देश हालात शांत करने पर जोर देते थे। वे हमारे साथ खड़े होकर और पाकिस्तान की आलोचना कर भारतीय जनता के रोष को शांत करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह परंपरा उसी दिन खत्म हो गई थी, जब डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुलाकर तथा शेष विश्व को अपने हाल पर छोड़ दिया। उप-महाद्वीप में कोई समस्या खड़ी होने पर ट्रंप संयम बरतने का ट्वीट भी फौरन नहीं करेंगे। इससे उपमहाद्वीप को विश्व से मिलने वाली यह राहत खत्म नहीं तो कम जरूर हो गई है कि 'आओ और हमें रोको नहीं तो हम एक-दूसरे पर परमाणु हमला कर देंगे'। दोनों देशों के जिम्मेदार परमाणु शक्तियां होने के दावे के बाद इस क्षेत्र के दुनिया को ब्लैकमेल करने का संदेह बढ़ रहा है। निस्संदेह, यह बात भारत से ज्यादा पाकिस्तान पर लागू होती है। क्योंकि इस उप-महाद्वीप में परमाणु हथियार कमजोर शक्ति या संभावित पराजित देश के तरजीही हथियार हैं। 1990 में वीपी सिंह से लेकर अब तक पाकिस्तान ने परमाणु धमकी का इस्तेमाल पूरी तरह अपने फायदे के लिए किया है। उसने अपने उकसावे को उस सीमा तक ही रखा है कि भारत की तरफ से बड़ा जवाबी हमला न हो।

परमाणु हथियारों का जुनून बताता है कि पाकिस्तानी शायद ही उस स्थिति की कभी समीक्षा करेंगे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें विनाशकारी अचंभा देखने को मिलेगा। यह भारतीय सरकार परमाणु हथियारों को केवल एक पक्ष के संयम के रूप में नहीं देखती है। अगर आपने दुस्साहस किया और वह भी चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले तो हो सकता है कि आपने अपनी कनपटी पर रखी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया हो।

साल के अंत तक बदल जाएगा भारतीय मीडिया का चेहरा

इस साल के अंत तक भारतीय मीडिया बाजार अलग नजर आने के साथ ही अलग तरह से काम भी करने लगेगा। इस साल सितंबर तक ज़ी एंटरटेनमेंट के 7,126 करोड़ रुपये के कारोबार का पांचवां हिस्सा कोई रणनीतिक निवेशक खरीद चुका होगा। इसी तरह 13,448 करोड़ रुपये के आकार का स्टार इंडिया भी 59.5 अरब डॉलर वाली वाल्ट डिज्नी की पूर्ण परिचालन अनुषंगी बन चुका होगा। वायकॉम18 का स्वामित्व रखने वाली 5,207 करोड़ रुपये की कंपनी नेटवर्क18 पहले से ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेजी से बढ़ते मीडिया पोर्टफोलियो का अंग बनी हुई है। रिलायंस समूह अपने मीडिया कारोबार के बारे में उठने वाले सवालों के जवाब शायद ही कभी देता है लेकिन केबल कंपनियों और फिल्म स्टूडियो समेत तमाम मीडिया परिसंपत्तियों को खरीदता रहा है। चर्चा चल रही है कि ज़ी एंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी खरीदने की होड़ में कॉमकास्ट और टेनसेंट के साथ रिलायंस भी शामिल है।

ज़ी, सोनी, स्टार, वायकॉम18 और सन ग्रुप के चैनलों की हिस्सेदारी भारत की कुल टीवी दर्शक संख्या की 74 फीसदी है। अगर आपको यह लगता है कि यह तो केवल टीवी कंपनियों का आंकड़ा है तो याद रखें कि भारत के 1.47 लाख करोड़ रुपये के आकार वाले मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में टीवी का हिस्सा 45 फीसदी है। शीर्ष पांच टीवी कंपनियों में ज़ी और स्टार सबसे आगे हैं। ज़ी के 37 चैनलों की कुल दर्शक संख्या में 20 फीसदी हिस्सेदारी है और वह पैसे कमाने में भी काफी आगे है। भले ही स्टार मुनाफा कमाने के मामले में उतना आगे नहीं है लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), कबड्डी, क्रिकेट प्रसारण और हॉटस्टार के रूप में उसके पास कमाई की भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं।

इस तरह देश की दो सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों के स्वामित्व ढांचे में जबरदस्त बदलाव होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है?

पहला, ज़ी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ पुनीत गोयनका कहते हैं, 'वर्ष 2020 तक मीडिया परिदृश्य बदल जाएगा। एकीकरण में तेजी आएगी लेकिन यह केवल चार बड़ी कंपनियों (स्टार, ज़ी, सोनी और वायकॉम) के भीतर ही रहेगा। आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनी 20 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है।' फिर तो हमें 6,500 करोड़ रुपये वाले सोनी और 3,105 करोड़ रुपये वाले सन ग्रुप की तरफ से थोड़ी धक्केबाजी पर नजर रखनी होगी। इन दोनों कंपनियों के विलय की चर्चा काफी पहले उठी थी लेकिन कुछ ठोस सामने नहीं आया। चर्चा यह है कि सोनी अपना विस्तार करने के लिए बाजार पर नजरें टिकाए हुए है। उसे ज़ी में एक संभावित निवेशक भी बताया जा रहा है।

दूसरा, इस घटनाक्रम से ऑनलाइन वीडियो परिसंपत्ति खड़ी करने की जंग तेज होगी। याद रखें कि अमेरिका में नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम वीडियो और अन्य खिलाड़ियों के विकास ने दुनिया के सबसे बड़े मीडिया उद्योग को भी झकझोर दिया है। अकेले नेटफ्लिक्स ने कंटेंट निर्माण पर पिछले साल 8 अरब डॉलर खर्च किए। ऐसे में परंपरागत मीडिया फर्मों को प्रसारण सामग्री खरीदने के लिए कॉमकास्ट, नेटफ्लिक्स, एमेजॉन या ऐपल के बरक्स कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। यह उन बड़े कारणों में शामिल रहा है जिसके चलते रुपर्ट मर्डोक ने 30 अरब डॉलर वाली अपनी कंपनी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स का मोटा हिस्सा पिछले साल डिज्नी को बेचने का फैसला किया था।

हालांकि भारत इस तरह के हालात पैदा होने से काफी दूर है। वर्ष 2018 में भारतीय बाजार में टीवी दर्शकों की संख्या 13 फीसदी बढ़ी। बार्क के आंकड़ों की मानें तो टेलीविजन दर्शकों की संख्या 83.6 करोड़ हो गई जबकि वर्ष 2016 में यह 79 करोड़ थी। ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले 44.7 करोड़ भारतीयों ने ऑनलाइन वीडियो देखने में करीब 50 मिनट लगाया जो टीवी देखने में प्रतिदिन दिए जाने वाले वक्त 3.45 घंटे से काफी कम है। वर्ष 2018 में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप के रफ्तार पकड़ने के बावजूद फिल्मों ने बढ़िया कारोबार किया था। असल में, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म का उदय फिल्म कारोबार के लिहाज से पूरक ही साबित हुआ है।

यहां एक और पहलू पर नजर डालनी होगी। नेटफ्लिक्स ने अमेरिकी बाजार में 8-12 डॉलर मासिक के किराये पर दस्तक दी थी जबकि उस समय औसत किराया 40-80 डॉलर चल रहा था। उसकी तुलना में भारत में टीवी देखने का मासिक खर्च अब भी 2-5 डॉलर ही है। इस तरह भारतीय बाजार में एक वीडियो ऐप को कीमत के मामले में कोई विशेष स्थिति नहीं हासिल है। हालांकि बाजार नियामक ट्राई के चैनलों का मूल्य तय करने वाले नए आदेश के बाद तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। नई व्यवस्था में दर्शकों को हरेक चैनल अलग-अलग लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिससे टीवी देखने का खर्च बढ़ जाएगा।

भुगतान राजस्व आने में वक्त लग सकता है लेकिन ऑनलाइन ऐप पर विज्ञापन जोर पकड़ने लगा है। गोयनका कहते हैं, 'औसतन एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लागत प्रति हजार के संदर्भ में 4-5 गुना दे देता है।' बड़े ऑनलाइन ऐप पर दिखने वाले विज्ञापनों की संख्या को देखें तो एक नया समानांतर कारोबार आकार लेता हुआ नजर आता है। कॉमस्कोर के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2018 में यूट्यूब के मासिक दर्शकों की संख्या 25.4 करोड़ और हॉटस्टार की दर्शक संख्या 7.9 करोड़ तक पहुंच गई थी। ज़ी के ओटीटी ऐप ज़ी5 ने दिसंबर में 5.6 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता होने का दावा किया है। भारत में तकनीक, मीडिया एवं दूरसंचार कंपनियों की तरफ से वित्त-पोषित करीब 35 वीडियो ऐप हैं। ऐसे में टेलीविजन बाजार के मुकाबले में विजयी होने वाले खिलाड़ियों के नाम तय होने में लंबा वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में इस कारोबार में बड़े पैमाने पर धन लगेगा। इसके लिए कर्ज या इक्विटी का रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे बाजार एकीकरण भी होगा।

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

कानाफूसी

क्रिया-प्रतिक्रिया

पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके और उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना करके राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी थी। इसके बाद लखनऊ में ऐसे पोस्टर लगे देखे गए जिन पर लिखा था कि देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को लोकसभा में रखने के लिए मुलायम सिंह यादव का धन्यवाद। उसी दिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव की रिश्तेदार राबड़ी देवी ने उनके बयान पर निराशा प्रकट की। उन्होंने कहा कि यादव ने जो कुछ भी कहा उसकी आज की राजनीति में कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि अब मुलायम की स्मृति उनका साथ छोड़ रही है।

किशोर का विस्तार

प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल ऐक्शन कमेटी (आई-पैक) राजनीतिक सलाह मशविरे के क्षेत्र में बहुत तेज गति से अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रही है और दिलचस्प है कि इसका किसी राजनीतिक विचारधारा से न जुड़ाव है और न ही दूरी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में आई-पैक को शिवसेना के साथ काम करने का प्रस्ताव मिल चुका है जबकि कई अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना है। जानकारी के मुताबिक आई-पैक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को नीतिगत सुझाव देने का काम भी करेगी।

आपका पक्ष

बेरोजगारी का स्थायी समाधान जरूरी

बेरोजगारी भारत की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है जिसे हल नहीं किया गया तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। इस समस्या का समाधान करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसके लिए सबसे बड़ी बाधा हमारी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बदलाव लाने होंगे। कॉलेज में सिद्धांत आधारित पढ़ाई होती है लेकिन उद्योगों के हिसाब से केवल सिद्धांत की पढ़ाई कारगर नहीं हो सकती। नौकरी और पढ़ाई के बीच यह खाई काफी गहरी होती जा रही है। असंगठित क्षेत्र में ठेकेदारी भी एक बड़ी समस्या है। इसके जरिये कामगारों का शोषण होता है और कम कर्मियों के सहारे अधिक काम कराया जाता है। कर्मियों और ठेकेदारों से जुड़ी प्रत्येक जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई एकड़ सरकारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। सरकार इसे पर्यटक स्थल या दूसरे कामों में उपयोग में ला सकती है और स्थानीय बेरोजगारों को काम दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई दूसरी समस्याएं भी हैं जिसके चलते गांवों से शहर में लगातार पलायन होता रहता है। सरकार भले ही प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का वादा करती रहे लेकिन उसके समय को लेकर कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। 10-12 घंटे तक लगातार बिजली गुल और एक बार खराबी आने पर 2-4 दिन तक बिजली का ना आना ग्रामीण क्षेत्रों में आम बात है। सरकार को इसका तत्काल समाधान करना चाहिए जिससे ग्रामीण, खासकर किसानों की स्थिति में सुधार होगा। सरकार के इन प्रयासों से नवयुवक रोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़े होंगे।

रविन्द्र कुमरावत, खरगोन

बेरोजगारी दूर करने के लिए असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का निदान जरूरी है

भवन निर्माण प्रक्रिया बने दुरुस्त

मकान बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री की बढ़ती कीमतों के चलते केंद्र सरकार की 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की योजना के सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। सरकार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रोत्साहन दे रही है और इसके चलते कई निर्माता घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। घटिया सामग्री के उपयोग के चलते कई निर्माण के गिरने की खबरें आती रहती हैं। इस तरह के निर्माताओं पर नकेल कसने के लिए सरकार को प्रभावी उपाय उठाने चाहिए। सरकार इसके लिए एक विशेष विभाग का गठन कर सकती है जो सामग्री की जांच और मजबूती का प्रमाणपत्र दे सके। निर्माताओं से एक राशि लेकर उसका कोष बनाया जाना चाहिए जिससे किसी हादसे की स्थिति में घायलों को मुआवजा दिया जा सके। दोषी निर्माताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाए और उनका लाइसेंस फौरन निरस्त किया जाए।

गुरदयाल सिंह, जम्मू

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।